भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 863

25 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी गयी राजसहायता

863 **श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) के प्रारंभ से अब तक दी गयी राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यू), निम्न आय समूहों (एल आई जी), और मध्यम आय समूहों (एम आई जी) को दी गयी राज सहायता का समूह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2022 तक 2.7 करोड़ आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, परंतु अब तक केवल 1.8 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है, जो लक्ष्य का लगभग 67 प्रतिशत है; और

(ङ) यदि हाँ, तो लक्ष्य प्राप्ति की विफलता के क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को सभी मौसमानुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता देने हेतु दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)-'सब के लिए आवास' मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /केंद्रीय नोडल एजेंसियों को

जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा और योजना के आरंभ से बाद से निर्मित आवासों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए योजना के तहत क्रमशः 81,027 करोड़ रु0, 26,168 करोड़ रु0 और 12,935 करोड़ रु0 की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

(घ) और (ड.): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए पीएमएवाई-यू के तहत मांग सर्वेक्षण किया है। योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आवासों की कुल निर्धारित मांग 112.24 लाख आवास थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मिशन अवधि के दौरान अर्थात दिनांक 31 मार्च 2022 तक कुल 122.69 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत आवासों में से, 101.94 लाख आवास निर्माणाधीन हैं; जिनमें से 61.15 लाख आवास पूरे किए गए/लाभार्थियों को वितरित कर दिए गए हैं।

योजना के विभिन्न घटकों में परियोजनाओं को पूरा करने में सामान्यत: 12-36 महीने लगते हैं। स्वीकृत कुल 122.69 लाख आवासों में से पिछले दो वर्षों में लगभग 41 लाख आवासों को स्वीकृत किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सभी आवासों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

*****

दिनांक 25-07-2022 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 863 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /केंद्रीय नोडल एजेंसियों को जारी केंद्रीय सहायता और निर्मित आवासों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रु0 में)**	**पूर्ण किए गए आवासों की संख्या**
2015-16	3,225.55	2,30,836
2016-17	4,574.27	1,29,111
2017-18	16,554.07	3,27,898
2018-19	25,070.92	18,16,669
2019-20	19,755.40	8,40,645
2020-21	26,612.56	14,51,670
2021-22	22,227.68	10,32,718
2022-23	2,109.97	2,85,672
कुल	**1,20,130**	**61,15,219**